

अर्ध न्यायकि नकिय

प्रलिमिस के लिये:

अर्ध न्यायकि नकिय, मध्यस्थता, न्यायाधिकरण बोर्ड, प्रशासनकि एजेंसी, कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, उपभोक्ता अदालत, कानूनी अधिकार, क्रत्तव्य, विशेषाधिकार, न्यायकि समीक्षा, राष्ट्रीय हरति न्यायाधिकरण, प्रदूषण, भारतीय निवाचन आयोग, मानवता प्राप्त दल, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), आयकर, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी), कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अधनियम, 1957, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी), दूरसंचार क्षेत्र, वित्त अधनियम, साइबर मामले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), सविल न्यायालय, मानवाधिकार, लोकपाल, बैंकगी वनियमन अधनियम, 1949, बैंकगी लोकपाल योजना, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी), सूचना का अधिकार अधनियम, 2005, कानून का नियम, विशेष एजेंसी, पारदर्शना, विधि आयोग, सविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

मेन्स के लिये:

न्याय प्रशासन में अर्ध न्यायकि नकियों की भूमिका और महत्व।

अर्ध न्यायकि नकिय क्या हैं?

प्रचिय:

- अर्ध न्यायकि नकिय गैर-न्यायकि संस्थाएँ हैं जिनके पास कानून की व्याख्या करने का अधिकार है।
- वे संगठन हैं, जिसे कि मध्यस्थता पैनल या न्यायाधिकरण बोर्ड, जो सार्वजनकि प्रशासनकि एजेंसियाँ हो सकती हैं और जिन्हें न्यायालय या न्यायाधीश के समान शक्तियाँ तथा प्रक्रियाएँ प्रदान की गई हैं।

विषेषताएँ:

- विवादों का समाधान:
 - वे मामलों में मध्यस्थता कर सकते हैं और दंड निधारति कर सकते हैं।
 - पक्षकार न्यायपालकि के पास जाने की प्रेशानी से गुजरे बना न्याय के लिये इन नकियों से संपर्क कर सकते हैं।
- सीमति निरिण्य शक्तियाँ:
 - उनका अधिकार आमतौर पर विशेषज्ञता के एक विशेषज्ञ क्षेत्र तक सीमति होता है, जैसे वित्तीय बाजार, रोजगार कानून, सार्वजनकि मानक, आवर्जन या वनियमन उदाहरण के लिये, कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण कॉर्पोरेट कंपनियों के शासन और कामकाज से संबंधित मामलों का फैसला करता है।
- पूर्व निधारति नियम:
 - अर्ध-न्यायकि नकियों के निरिण्य और फैसले अक्सर पूर्व निधारति नियमों पर निभर होते हैं।
 - उनके निरिण्य मौजूदा कानून के नियमों पर आधारति होते हैं।
- दंड देने का अधिकार
 - उनके पास अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों में दंड देने का अधिकार है, जैसे भारत में उपभोक्ता न्यायालय उपभोक्ता विवादों से निपटा है और अवैध गतविधियों में लिप्त कंपनी को दंडित करता है।
- न्यायकि समीक्षा:
 - इन नकियों द्वारा जारी किये गए नियमों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा न्यायपालकि का निरिण्य सर्वोच्च होता है।
- गैर-न्यायकि प्रमुख:
 - न्यायपालकि के विवित, जिसका नेतृत्व न्यायाधीश करते हैं, इन नकियों का नेतृत्व वित्त, अर्थशास्त्र और कानून जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ करते हैं।

अधिकार

- सुनवाई का संचालन: वे साक्षय एकतर करने और गवाहों की गवाही सुनने के लिये सुनवाई का संचालन कर सकते हैं।
- तथ्यात्मक निधारण: अर्ध-न्यायकि प्राधिकारी सुनवाई में प्रस्तुत साक्षय के आधार पर प्रासंगिकि तथ्यात्मक निधारण कर सकते हैं।
- कानून लागू करना: वे अपने द्वारा निधारति तथ्यों पर कानून लागू कर सकते हैं और संबंधित पक्षों के कानूनी अधिकारों,

कर्तृतव्यों या वशिष्ठाधकिराँ के संबंध में नरिणय ले सकते हैं।।

- आदेश या नरिणय जारी करना: वे ऐसे आदेश या नरिणय जारी कर सकते हैं जिनका कानूनी बल हो, जैसे कसी पक्ष को हरजाना देने या कुछ शर्तों का पालन करने के लिये बाध्य करना।
- नरिणयों को लागू करना: वे अपने नरिणयों को लागू करने के लिये कदम उठा सकते हैं, जैसे किंगर-अनुपालन हेतु जुरुमाना या अन्य दंड लगाना।

■ लाभ:

- लागत प्रभावी: पारंपरिक अदालतों की तुलना में न्यायाधकिरण अधिक लागत प्रभावी है, जो लोगों को न्याय पाने और अपनी शक्तियों को हल करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।
- परेशानी मुक्त: वे सुलभ हैं, तकनीकी जटिलताओं से मुक्त हैं और वे वशिष्ठज्ञ प्रयोक्षण के तहत अधिक तेज़ी से और कुशलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं।
- न्यायिक कार्यभार में कमी: कई मामलों पर नरिणय लेने वाले न्यायाधकिरण न्यायपालिका के कार्यभार को कम करते हैं, उदाहरण के लिये [राष्ट्रीय हरति अधिकारण](#) प्रयोक्षण से संबंधित मामलों पर नरिणय देता है।
- शीघ्र न्याय: वे वशिष्ठज्ञता, केंद्रित कषेत्राधिकार और कम औपचारिकताओं के माध्यम से शीघ्र न्याय प्रदान करते हैं।

■ भारत में महत्वपूर्ण अर्द्ध-न्यायिक निकायों की सूची:

- भारतीय नरिवाचन आयोग (ECI):
 - अपने अर्द्ध-न्यायिक कषेत्राधिकार के एक भाग के रूप में, [भारतीय नरिवाचन आयोग](#) मान्यता प्राप्त दलों के अलग-अलग समूहों के बीच विवादों का नपिटारा करता है।
 - इसमें ऐसे अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है जो विधिद्वारा निर्धारित समय और तरीके से अपनेचुनाव व्यय का लेखा-जोखा परस्तुत करने में विफल रहता है।
- आयकर अपीलीय अधिकारण (ITAT):
 - यह आयकर प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर करने हेतु एक अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारण है।
 - आयकर विभाग, आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारति कसी भी आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय अधिकारण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
- बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (IPAB):
 - बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (Intellectual Property Appellate Board- IPAB) कॉर्पोरेइट पंजीकरण, कॉर्पोरेइट असाइनमेंट तथा जनता से छपिए गए कार्यों हेतु लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित विवादों पर नरिणय लेने के लिये जमिमेदार है।
 - यह [कॉर्पोरेइट अधिनियम, 1957](#) के अंतर्गत अपने समक्ष लाए गए अन्य विधि मामलों की भी सुनवाई करता है।
- दूरसंचार विवाद नपिटान एवं अपीलीय न्यायाधकिरण (TDSAT):
 - वर्ष 2004 में प्रसारण मामलों को शामिल करने के लिये TDSAT के अधिकार क्षेत्र का वसितार किया गया।
 - [वित्त अधिनियम, 2017](#) के माध्यम से TDSAT के अधिकार क्षेत्र को एयरपोर्ट ट्रैफि तथा [साइबर मामलों](#) तक बढ़ा दिया गया।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC):
 - [NHRC](#) के पास एक [सविलि न्यायालय](#) की शक्तियाँ हैं। यह मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में कसी भी दस्तावेज़ की मांग कर सकता है तथा कसी भी व्यक्तिको सम्मन भेज सकता है।
 - मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में इसकी सफिराशिं दो प्रकार की हैं अर्थात् पीड़ितों को राहत और दोषियों को सजा।
- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC):
 - [CIC, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005](#) के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा लिये गए नरिणयों के विरुद्ध शक्तियों और अपीलों की सुनवाई के लिये अंतमि अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।

न्यायिक तथा अर्ध-न्यायिक निकायों के बीच अंतर:

आधार	न्यायिक निकाय	अर्ध-न्यायिक निकाय
प्राधिकार	यह एक न्यायालय है जिसके पास कानून की व्याख्या करने और उसे लागू करने, मामलों की सुनवाई करने तथा नरिणय देने एवं नरिणयों को लागू करने का अधिकार है।	यह एक ऐसी या न्यायाधकिरण है जो न्यायालय की तरह कार्य करता है, विवादों का नपिटारा करने के साथ नरिणयों को लागू करता है।
स्वतंत्रता	यह सरकार की कार्यकारी एवं विधायी शाखाओं से स्वतंत्र है और साथ ही कानून का शासन को बनाए रखने के लिये भी जमिमेदार है।	यह पूर्ण न्यायालय नहीं है और साथ ही इसकी स्वतंत्रता भी कम है। सरकार की कार्यकारी एवं विधायी शाखाओं का इस पर अधिक नियंत्रण होता है।
अधिकार क्षेत्र	उनके पास सविलि तथा आपराधिक मामलों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है।	उनका अधिकार क्षेत्र सीमित है और वे केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जो उनकी वशिष्ठज्ञता या विधि-वस्तु के वशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
नरिणय लेने का आधार	उनके पास नई कानूनी मसिल कायम करने की शक्ति है जिसका उपयोग भविष्य के मामलों में किया	उनके नरिणय वशिष्ट मामले पर विधिमान कानूनों को लागू करने तक सीमित होते हैं।

	जा सकता है।	
न्यायाधीश	इसमें सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीश या न्यायकि मजिस्ट्रेट शामलि होते हैं।	इसमें सरकार द्वारा या कसी वशिष्ठ एजेंसी द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों एवं वशिष्ठज्ञों का एक संयोजन शामलि हो सकता है।
कठोरता	ये प्रायः अधकि औपचारकि होते हैं और प्रक्रयि के कठोर नियमों का पालन करते हैं।	हालाँकि ये न्यायकि निकाय की अपेक्षा कम औपचारकि होते हैं किंतु फरि भी ये निर्धारत प्रक्रयिओं और साक्ष्य के नियमों का पालन करते हैं।

अरद्ध-न्यायकि निकायों से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- सीमित जनशक्ति:** प्रायः इन निकायों में क्रमचारियों की संख्या कम होती है और मामले अधकि होते हैं, जिससे शीघ्र न्याय प्रदान करना मुश्किल हो जाता है।
- अपील तंत्र:** अधिकिरणों के विविध और लिये गए नियमों को प्रायः न्यायालयों में चुनौती दी जाती है, जिससे अरद्ध-न्यायकि निकाय का प्रयोजन कमज़ोर होता है।
- झूठे मामले:** हालाँकि अधिकिरणों की कम लागत लोगों को न्याय पाने के लिये प्रोत्साहित करती है किंतु इसके परिणामस्वरूप कई ऐसे दावे भी दायर होते हैं जो निराधार होते हैं।
- एकरूपता का अभाव:** विभिन्न निकायों में मौजूद प्रक्रयिओं और मानक की असंगतता से एकरूपता का अंतराल बढ़ता है तथा अप्रत्याशिता उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- क्रमचारियों की संख्या में वृद्धि:** मामलों के कुशलतापूर्वक नियोजन के लिये इन निकायों में क्रमियों की अधकि नियुक्ति करने की आवश्यकता है। इसमें न्यायाधीश, क्लर्क और सहायक क्रमचारी शामलि हैं।
- अपील हेतु स्पष्ट दर्शा-निर्देश:** तुच्छ चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से कब और कसी प्रकार नियमों की अपील की जा सकती है, इसके संबंध में स्पष्ट दर्शा-निर्देश तथा मानदंड स्थापित करने की आवश्यकता है।
- सक्रीयि तंत्र:** कार्यवाही को आगे बढ़ने से पहले आधारहीन दावों की पहचान करने और उन्हें प्रतिचिछादति (Filter) करने के लिये शुरुआत में ही सक्रीयि (छानबीन करना अथवा छाँटना) प्रक्रयिएँ क्रयियान्वित करने की आवश्यकता है। प्रणाली के दुरुपयोग की रोकथाम करने हेतु झूठे अथवा तुच्छ मामले दर्ज करने वालों के लिये दंड निर्धारित कर उनका क्रयियान्वन किया जाना चाहयि।
- मानकीकृत प्रक्रयिएँ:** निकायों में संगतता/सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिये सभी अरद्ध-न्यायकि निकायों में मानकीकृत प्रक्रयिएँ और दर्शा-निर्देश तैयार कर उन्हें क्रयियान्वित करने की आवश्यकता है।
- अंतर-निकाय समन्वय:** सरकारी प्रथाओं को साझा करने और प्रक्रयियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये विभिन्न अरद्ध-न्यायकि निकायों में समन्वय तथा संचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- केस प्रबंधन प्रणाली:** मामलों को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने और प्रशासनिक दरी को कम करने हेतु मामले के प्रबंधन के लिये उन्नत प्रणाली क्रयियान्वित करने की आवश्यकता है।
- नियमिति अंकेक्षण:** नियमों के नियोजन का आकलन करने और संभावित सुधार की पहचान करने के लिये अरद्ध-न्यायकि निकायों का नियमिति अंकेक्षण तथा मूल्यांकन किया जाना चाहयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न: अरद्ध-न्यायकि (न्यायकिवत्) निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिये। (2016)

प्रश्न: भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सरकारी अधिकारी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकित्वों (मैकेनिज्म) का प्रयोग समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोत्तरता करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका तथा अन्य संस्थानों के प्रभावी पूरक के तौर पर एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिये। (2014)

प्रश्न: यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फरि भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए, सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिये। (2021)

प्रश्न: “केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के क्रमचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शक्तियों एवं प्रवादों के नियमिति हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायकि प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।” व्याख्या कीजिये। (2019)

प्रश्न: आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारता को कम कर सकते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/quasi-judicial-body>

